

Eastern Railway
(Personnel Department)

Serial Circular No. 63/2015

No. E.406/0/Pt.II

Kolkata, Dated: 08/06/2015

All Concerned

Sub: Grant of honorarium to the Inquiry Officer (IO) and Presenting Officer (PO) for conducting Departmental Inquiries in cases other than Vigilance Investigation.

Railway Board's instructions contained in letter No. E(G) 2012/HO1-13 dated 07.05.2015 (**RBE No. 44/2015**) on the above noted subject are reproduced below for information, guidance and necessary action. Board's earlier letter No. 2009/V-1/DAR/6/1 dated 22.09.2011 (RBV No. 12/2011) mentioned therein was circulated under GM(Vigilance)/ER, Kolkata's confidential letter No. G.157/STAFF/POLICY/II/RIO/PT.II dated 09/11.11.2011.

DA: Hindi version.



(S. K. Chattopadhyay)
Asstt. Personnel Officer/HQ
For Chief Personnel Officer
Phone No. 24122

Copy of Board's letter No. E(G) 2012/HO1-13 dated 07.05.2015 (RBE No. 44/2015) addressed to the GM (P)/All Zonal Railways & others.

Sub: Grant of honorarium to the Inquiry Officer (IO) and Presenting Officer (PO) for conducting Departmental Inquiries in cases other than Vigilance Investigation.

Proposals have been received from various Railways for extending the provision for grant of honorarium to the Inquiry Officer (IO) and Presenting Officer (PO) for conducting Departmental Inquiries in cases other than vigilance investigations.

2) The issue has been considered by the Board and it has now been decided that Non-Vigilance administrative cases also qualify for the same remuneration as applicable to the Vigilance cases as issued vide Board's letter No. 2009/V-1/DAR/6/1 dated 22.09.2011.

2.1) The rates of honorarium for various posts as and when enhanced by Vigilance Directorate, will automatically be applicable to those conducting Non Vigilance cases.

3) The rates of Non-Vigilance cases will be applicable from the date of issue of the letter.

4) This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways

Sd/(S. Pal)
Jt. Director Estt. (G)/Railway Board.

INDEX No.1040: Non-Vigilance administrative cases also qualify for the same remuneration as applicable to the Vigilance cases.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी) 2012/एचओ 1-13

नई दिल्ली, दिनांक 7.05.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

(डाक सूची के अनुसार)

विषय: सतर्कता जाँच-पड़ताल से इतर मामलों में विभागीय जाँच करने के लिए पूछताछ अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को मानदेय प्रदान करना।

सतर्कता जाँच-पड़ताल से इतर मामलों में विभागीय जाँच करने के लिए पूछताछ अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को भी मानदेय प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए विभिन्न रेलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

2) बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और अब यह विनिश्चय किया गया है कि गैर-सतर्कता संबंधी प्रशासनिक मामलों में भी वही पारिश्रमिक लागू होगा जो बोर्ड के दिनांक 22.09.2011 के पत्र सं. 2009/V-1/डीएआर/6/1 के तहत जारी सतर्कता मामलों के लिए लागू होगा।

2.1) जब कभी सतर्कता निदेशालय द्वारा विभिन्न पदों के लिए मानदेय की दरों में वृद्धि की जाएगी तो गैर सतर्कता मामलों का संचालन करने वालों के लिए भी यह स्वतः ही लागू हो जाएगा।

3) गैर सतर्कता मामलों की दरें इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगी।

4) इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

सुभोतोष पाल

(एस.पाल)

संयुक्त निदेशक ई(जी)

सं. ई(जी) 2012/एचओ 1-13

नई दिल्ली, दिनांक 7.05.2015

1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

सुभोतोष पाल

(एस.पाल)

संयुक्त निदेशक ई(जी)

.....2/-